

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर0ए0एस0



निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 47 / 16

1. जगदीश
2. कालूराम पिसरान धर्मपाल
3. रामजी लाल
4. अमीचन्द पिसरान जगराम
5. लीलाधर
6. मदन लाल
7. लालचन्द पिसरान पन्नाराम
8. संजीव कुमार पुत्र साहबराम अकवाम जाट सकनाए मन्नीवाली
9. राजू उर्फ प्रवीण पुत्र मंगतराम जाति बाघला निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1 विकास अधिकारी ,पंचायत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 2.सरपंच, ग्राम पंचायत मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश विकास अधिकारी, सादुलशहर दिनांक 23-04-12

- उपस्थित :
1. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता निगरानीकर्तागण
 2. राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 एक
 3. श्री दुर्गाप्रसाद, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 दो

आदेश

दिनांक : 25 -1-17

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निगरानीकृत आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्तागण को पट्टे जारी किये गये हैं। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा बिना जाँच किये शिकायत के आधार पर निगरानीकृत आदेश पारित किया गया है। राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी में गैरमुमकिन आबादी दर्ज है। वार्ड सं0 9 जोहड़ पायतन का स्थान नहीं है। निगरानीकर्तागण आवंटित पट्टों पर काबिज हैं। निगरानीकृत आदेश पारित करने का अधिकार अप्रार्थी सं0 एक को नहीं था। निगरानीकृत आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है एवं बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व न तो कोई नोटिस दिया गया है और न ही विधिवत् सुनवाई की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन अप्रार्थी सं0 1 से प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्तागण को पट्टे जारी किये गये हैं। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा बिना जाँच किये शिकायत के आधार पर निगरानीकृत आदेश पारित किया गया है। राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी में गैरमुमकिन आबादी दर्ज है। वार्ड सं0 9 जोहड़ पायतन का स्थान नहीं है। निगरानीकर्तागण आवंटित पट्टों पर काबिज हैं। निगरानीकृत आदेश पारित करने का अधिकार अप्रार्थी सं0 एक को नहीं था। निगरानीकृत आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है एवं बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व न तो कोई नोटिस दिया गया है और न ही विधिवत् सुनवाई की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

(Signature)
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (प्रशासन)

अप्रार्थी सं० 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्तागण को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् रूप से पट्टे जारी किये गये हैं तथा निगरानीकर्तागण पट्टे शुदा भूमि पर काबिज हैं। पट्टों को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकृत आदेश क्रमांक 364 दिनांक 23-4-12 जो अप्रार्थी सं० 1 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर द्वारा अप्रार्थी सं० 2 ग्राम पंचायत मन्नीवाली को जारी किया गया है, में वर्णित किया गया है कि ग्राम पंचायत मन्नीवाली के निवासियों द्वारा वार्ड सं० 9 के सार्वजनिक जोहड़ पर अतिक्रमण करने की प्रस्तुत शिकायत के क्रम में आदेशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सार्वजनिक जोहड़ इत्यादित की भूमि सुरक्षित रखी जावे। उक्त जोहड़ स्थल पर यथास्थिति बनाना सुनिश्चित करें। उक्त स्थल पर कब्जे का प्रयास कर रहे अप्रार्थीगण से उक्त भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेज प्राप्त किये जावें। यदि उक्त भूमि के पट्टे जारी कर दिये गये हैं तो राजस्थान पंचायत राज नियमानुसार उन्हें निरस्त कराने की कार्यवाही की जावे एवं पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता (बीडीओ सादुलशहर) को अविलम्ब अवगत कराया जावे।

उक्त निगरानीकृत आदेश में अप्रार्थी सं० 1 द्वारा जोहड़ स्थल पर यथास्थिति बनाने का आदेश दिया गया है। साथ ही यदि उक्त भूमि पर पट्टे जारी कर दिये गये हैं तो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें निरस्त कराने की कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है।

अप्रार्थी सं० 1 ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 11-11-16 में अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत मन्नीवाली के रिकार्ड में उक्त स्थल के संबंध में खसरा रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। राजस्व रेकार्ड में जोहड़ दर्ज नहीं है, लेकिन मौके पर देखने पर भी स्थिति पानी वाली जगह प्रतीत होती है।

विकास अधिकारी, सादुलशहर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 11-11-16 में स्वयं यह माना है कि ग्राम पंचायत मन्नीवाली के रिकार्ड में उक्त स्थल के संबंध में खसरा रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। राजस्व रेकार्ड में जोहड़ दर्ज नहीं है जबकि ग्राम पंचायत के अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्तागण को विधिसम्मत कार्यवाही कर पट्टे जारी किये गये हैं और निगरानीकर्तागण अपने -2 पट्टों की भूमि पर काबिज हैं। खसरा आवादी का रेकार्ड उपलब्ध न होने व राजस्व रेकार्ड में जोहड़ दर्ज न होने से यह स्थिति स्पष्ट नहीं होती है कि निगरानीकर्तागण को जोहड़ की भूमि में पट्टे जारी किये गये हैं। अप्रार्थी सं० 1 द्वारा विना विधिवत् जाँच किये, विना सुनवाई किये निगरानीकृत आदेश पारित किया गया है। विना सारवान दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यथास्थिति का स्थगन पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है और ऐसा आदेश विना क्षेत्राधिकारिता के है। विकास अधिकारी तथ्यपरक जाँच कर यह सुनिश्चित करते कि निगरानीकर्तागण को जो पट्टे जारी किये गये हैं, वे जोहड़ पायतन की भूमि पर हैं। ऐसा तथ्य प्रमाणित होने पर पृथक-2 पट्टे के विरुद्ध राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 97 के अन्तर्गत निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर विधिसम्मत कार्यवाही कर सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा निगरानीकृत आदेश जो विकास अधिकारी, सादुलशहर द्वारा जरिये क्रमांक 364 दिनांक 23-4-12 को विना विधिवत् सुनवाई किये, विना क्षेत्राधिकारिता के पारित किया गया है, को निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर एवं ग्राम पंचायत मन्नीवाली को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 25-1-17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/1/17
 (करतारसिंह पूनिया)
 अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
 अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
 अति० जिला कलक्टर (राजस्थान)